



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 1978/ज्याइस्था 2, 1900

No. 159]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 1978/JYAISTHA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 1978

सां० का० नि० 298(अ) —राष्ट्रपति द्वारा 20 मई, 1978 को दिया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 371-ब के खंड (3) और (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण आदेश, 1975 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) आदेश, 1978 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण आदेश, 1975 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल आदेश कहा गया है), पैरा 7 के उपपैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) इस पैरा के अधीन प्रत्येक अभ्यावेदन शपथपत्र से समर्थित याचिका के रूप में होगा और उसके साथ पचास रुपए मूल्य के स्टाम्पों के रूप में न्यायालय फीस संलग्न होगी।

परन्तु ऐसे व्यक्ति से जो इस आदेश के पैरा 6 में निर्दिष्ट कोई लोक पद धारण करता है या धारण किया है और जो तीन सौ रुपए प्रतिमास से कम, वेतन, यथास्थिति, लेता है या ऐसा लोक पद धारण करते हुए अंतिम दिन, ले रहा था, किसी फीस के संदाय की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

परन्तु यह और कि जहां अधिकरण अभ्यावेदन ग्रहण करने से इन्कार कर देता है वहां वह अपने विवेकानुसार, इस प्रकार संदस फीस के प्रति-दाय का आदेश कर सकेगा।”।

3. मूल आदेश के पैरा 10 में—

(1) उप पैरा (2) में, परन्तु के स्थान पर निम्नलिखित परन्तु रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“परन्तु, कोई अकेला सदस्य—

(1) इस आदेश के पैरा 14 के अधीन उच्च न्यायालय या राज्य के किसी अन्य सिविल न्यायालय से अधिकरण को स्थानान्तरित कार्य-वाही की सुनवाई कर सकता है और उसका विनिश्चय कर सकता है ;

(2) किसी ऐसे मामले की बाबत जिसकी इस पैरा के उप-पैरा (3) और (4) के अधीन खंड न्यायपीठ या पूर्ण न्यायपीठ द्वारा सुनवाई की जानी है और विनिश्चय किया जाना है कोई अभ्यावेदन या याचिका आरम्भित, स्वीकार कर सकता है किन्तु विनिश्चय नहीं कर सकता है और सम्बद्ध पक्षकार को अंतरिम अनुमोष अनुवृत्त करने वाला आदेश कर सकता है या इस प्रकार किए गए किसी आदेश को उपान्तरित अथवा प्रतिसंहृत कर सकता है ;

परन्तु यह और कि वह सदस्य जिसके समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगाया गया है, किसी भी समय खंड न्यायपीठ या पूर्णन्यायपीठ द्वारा उसकी सुनवाई और विनिश्चय किए जाने के लिए उसे स्थगित कर सकता है।”।

(2) उप पैरा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखे जाएंगे अर्थात् :—

“(3) आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काइरो का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 के उपबंधों से

संबंधित या उनके प्रयोग में उद्भूत होने वाले किसी मामले को, जो ऐसा मामला नहीं है जिसकी इस पैरा के उप पैरा (4) के अधीन पूर्णन्यायापीठ द्वारा सुनवाई और विनिश्चय किया जाता है, खंड न्यायापीठ द्वारा सुनवाई और विनिश्चय किया जा सकता है :

परन्तु यदि न्यायापीठ के दोनों सदस्य इस बात में सहमत हैं कि विनिश्चय में पर्याप्त महत्व का प्रश्न अंतर्बलित है तो वे आदेश कर सकते हैं कि प्रश्नगत मामले या प्रश्न को पूर्णन्यायापीठ को निर्दिष्ट कर दिया जाए।

(4) पूर्ण न्यायापीठ ऐसी न्यायापीठ होगी जिसमें तीन से कम सदस्य नहीं होंगे और पूर्ण न्याय पीठ द्वारा निम्नलिखित मामलों की सुनवाई और विनिश्चय किया जाएगा, अर्थात् :—

- (1) आंध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काइंगे का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के किन्हीं उपबंधों के निर्वहन से संबंधित मामले ;
- (2) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) के उपबंधों के परिणामस्वरूप राज्य सेवाओं के एकीकरण से उद्भूत होने वाले सभी मामले ;

- (3) कोई अन्य मामले जो उसे सीधे जाएं या निर्दिष्ट किए जाएं।”

राष्ट्रपति भवन,

नई दिल्ली।

20 मई, 1978

नीलम सजीव रेड्डी

भारत का राष्ट्रपति

[सं० IV/11015/13/76-एस० एंड पी० (डी०-5)/एग आर]

प्रमोद प्रकाश श्रीवास्तव, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 1978

G.S.R. 298(E).—The following Order made by the President on the 20th May, 1978 is published for general information :—

ORDER

In exercise of the powers conferred by clauses (3) and (4) of article 371-D of the Constitution, the President hereby makes the following Order to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal Order, 1975, namely :—

1. (1) This Order may be called the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Amendment) Order, 1978.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Andhra Pradesh Administrative Tribunal Order, 1975, (hereinafter referred to as the principal Order), in paragraph 7, for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

- “(3) Every representation under this paragraph shall be in the form of a petition supported by an affidavit and shall be accompanied by court fee stamps of the value of Rs. 50.00 ;

Provided that no person who holds, or has held, any public post referred to in paragraph 6 of this Order and who draws, or was drawing on the last day while holding such public post, as the case may be, a pay of less than Rs. 300 per mensem shall be required to pay the fees :

Provided further that where the Tribunal refuses to admit a representation, it may, in its discretion, order the refund of the fees so paid.”

3. In paragraph 10 of the principal Order—

- (i) in sub-paragraph (2), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely :—

“Provided that a single member may,—

- (i) here and determine the proceedings transferred to the Tribunal from the High Court or any other civil court in the State under paragraph 14 of this Order ;
- (ii) initially admit, but not determine, a representation or petition in relation to any matter which is required to be heard and determined under sub-paragraphs (3) and (4) of this paragraph by a Division Bench or a Full Bench and make an order granting interim relief to the party concerned or modify or revoke any order so made :

Provided further that the member before whom the matter is posted for hearing may at any time adjourn it for hearing and determination by a Division Bench or a Full Bench.” ;

- (ii) for sub-paragraphs (3) and (4), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely :—

“(3) Any matter relating to or arising out of the application of the provisions of the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975, not being a matter which is required to be heard and determined by a Full Bench under sub-paragraph (4) of this paragraph, may be heard and determined by a Division Bench :

Provided that if both the members of a Bench agree that the determination involves a question of substantial importance, they may order that the matter or question at issue be referred to a Full Bench.

- (4) A Full Bench shall be a Bench of any number not less than three of the members and the following matters may be heard and determined by a Full Bench, namely :—

- (i) matters involving the interpretation of any of the provisions of the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975 or any order made thereunder ;
- (ii) all matters arising out of the integration of any services of the State consequent on the provisions of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956) ;
- (iii) any other matter which is assigned to, or referred to, it.”

Rashtrapati Bhavan,
New Delhi.
20th May, 1978.

N. SANJIVA REDDY, President
[F. No. IV/11015/13/76-S&P(D-V)/SR]
P. P. SHRIVASTAV, Jt. Secy.